नगरपरिषद 70 हजार पौधे लगायेगी

सुजानगढ, (निसं)। नाथो तालाब स्थित ग्रीन स्पेस पार्क में सभापति नीलोफर गौरी ने पौद्यारोपण कर नगरपरिषद के पौद्यारोपण अभियान की शुरूआत की। इस दौरान सभापति ने बताया कि परिषद द्वारा ग्रीन स्पेस पार्क में पांच सौ पौद्ये लगाये जायेंगें तथा नगरपरिषद क्षेत्र में 70 हजार पौद्ये लगाये जायेंगे। नरेगा श्रमिकों द्वारा पौद्यों की देखभाल एवं संरक्षण किया जायेगा। इस दौरान परिषद के सचिव सुरेश चौहान, एटीपी उदयसिंह गुर्जर, सहायक लेखाधिकारी भंवरलाल मेहरडा, कनिष्ठ अभियंता कमलेश कुमार, एसआई ओमप्रकाश स्वामी, मुन्नालाल मीणा, तिलोक चंद, पवन कुमार रांकावत, इरशाद गौरी, पार्षद आसिफ चौहान, मोहन मेघवाल, जाकिर क्याल, शहरी मनरेगा के जेटीए यतेन्द्र सिंह, कृष्ण शर्मा, नरपत सिंह, सरिता, मनीषा सहित अनेक नगरपरिषद कार्मिक, जनप्रतिनिधि एवं नरेगाकर्मी मौजूद थे।

इसी प्रकार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के76 वें स्थापना दिवस पर सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान छात्राओं को पौद्ये वितरित किये गये। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. साधना सिंह, एबीवीपी के प्रांत कार्यसमिति सदस्य राहुल सामरिया, जिला संयोजक विशाल, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य देवांश एवं स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।

राज्य की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने वाला है बजट : राजेन्द्र राठौड़

■ पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने बजट 2024-25 पर प्रतिक्रिया दी

चूरू, (कासं)। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने राजस्थान की वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा सदन में प्रस्तुत राज्य बजट 2024-25 पर प्रतिक्रिया दी है। राठौड़ ने इसे राज्य की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने वाला विकासोन्मुखी व जनकल्याणकारी बताते हुए मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राठौड़ ने कहा कि राज्य की भजनलाल सरकार द्वारा प्रस्तुत पहला पूर्णकालिक बजट 2024-25 जन-जन की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने वाला है। यह आपणो अग्रणी राजस्थान की संकल्पना की सिद्धि को समर्पित लोक-कल्याणकारी व सर्वसमावेशी संकल्पों को धरातल पर साकार करेगा एवं नये व सशक्त राजस्थान के निर्माण की नींव रखते हुए राज्य के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

राठौड़ ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार द्वारा प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति हेतु चूरू सहित प्रदेश में 132 केवी जीएएस व लाइनों के निर्माण की स्वीकृति से जिले में पर्याप्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। 15 करोड़ रुपए की लागत से चूरू की सड़कों के सुदृढ़ीकरण और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए तारानगर शहर व क्षेत्रों की विभिन्न सड़कों व मिसिंग लिंक का कार्य और 200 करोड़ की लागत से तारानगर रोड़ से वाया भालेरी रोड़ वाया सरदारशहर रोड़ वाया रतनगढ रोड़ वाया देपालसर रोड़ से नेशनल हाईवे 52 चूरू तक रिंग रोड़ का निर्माण किया जायेगा। 75 करोड़ की लागत से बाइपास एनएच . 58 से मेगा हाइवे सुजानगढ़ चूरू का निर्माण कार्य व 5-5 करोड़ रुपए की की लागत से राम नगर तिराहा चूरू और ओम कॉलोनी में चूरू में आरओबी का निर्माण, 7 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से मोलीसर रतनगढ़ रेलवे स्टेशन चूरू पर आरओबी 75 निर्माण कराया जाएगा। यह हाइवे, आरओबी और सड़कें चूरू के विकास के नए मार्गों को प्रशस्त करेंगे और शहरवासियों के आवागन को सुलभ बनाएगी तथा शहर में जगह जगह लगने वाले जाम की परेशानी से भी निजात मिलेगी।

राठौड़ ने कहा कि देश और प्रदेश में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र चूरू के सालासर मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य धार्मिक और पर्यटन को बढ़ावा देने में सार्थक होगा और कृषि के क्षेत्र में अहम स्थान रखने वाले चूरू में कृषि महाविद्यालय खुलने से जिले के विद्यार्थियों को उन्नत खेती और किसानी के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बेहतर अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य के जरिए चूरू में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए गढ़ चूरू के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सैटेलाइन चिकित्सालय में क्रमोन्नयन होने यहां के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। 100 करोड़ की लागत से सरदारशहर चूरू मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को उन्नत व सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

चिड़ावा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया

चिड़ावा, (निसं)। उत्तर पश्चिम रेलवे ने एडीआरएम संजीव दीक्षित आज चिड़ावा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। दीक्षित शाम के समय चिड़ावा पहुंचे। स्टेशन अधीक्षक आजाद सिंह ने उनका स्वागत किया। दैनिक रेल यात्री संघ सदस्यों ने अध्यक्ष देवेंद्र वर्मा के नेतृत्व में साफा और माला पहनाकर दीक्षित का अभिनंदन किया। एडीआरएम संजीव दीक्षित स्टेशन दफ्तर में सिग्नल प्रक्रिया, स्टोर रूम, रिटायरिंग रूम, ई टिकटिंग प्रणाली, स्टेशन के बाहर पौधारोपण सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली और स्टेशन अधीक्षक आजाद सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एडीआरएम संजीव दीक्षित को दैनिक रेलयात्री संघ चिड़ावा अध्यक्ष देवेन्द्र वर्मा ने विभिन्न मांगों के लिए ज्ञापन दिया। एडीआरएम संजीव दीक्षित ने सभी मांगों को ध्यानपूर्वक पढ़ा और इनको जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया।

पुरानी पेंशन को लेकर विद्युत श्रमिक संघ की बैठक

झुंझुनूं, (निसं)। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ जिला झुंझुनूं के अधीक्षण अभियंता वृत्त कार्यालय परिसर में पुरानी पेंशन को लेकर बैठक संपन्न हुई। बैठक श्रमिक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में वृत्त कार्यालय परिसर संघ के जिला महामंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि पुरानी पेंशन बिजली कर्मचारियों का अधिकार है। परंतु जीपीएफ कटौती चालू नहीं की गई। इसके लिए जल्द जयपुर मुख्यालय विद्युत भवन पर प्रदर्शन किया जाएगा तथा श्रमिक समस्याओं पर चर्चा की गई। समस्याओं के निदान के लिए अधीक्षण अभियंता से वार्ता कर निस्तारण के लिए आश्वस्त किया गया। बैठक में उपस्थित डिस्कॉम महामंत्री देवकरण सैनी की अनुमति से अधीक्षण अभियंता कार्यालय परिसर वृत्त इकाई की कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। जिसमें हजारीलाल सैनी को संरक्षक, मूलचंद महला को अध्यक्ष तथा रामावतार शर्मा को सचिव उपस्थित रहे।

कार्यालय नगर परिषद, झुन्झुनू (राज.)

कमांक:-एफ-6 भूमि ( )/2024-25/3553 दिनांक :- 05.07.2024

पट्टा निरस्तीकरण आदेश

कार्यालय हाजा द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान स्टेशन रोड के पूर्व का क्षेत्र में स्थित भूखण्ड संख्या 07, क्षेत्र. 700.00 वर्गगज का पट्टा विलेख दिनांक 21.06.2013 को श्री संदीप ,प्रदीप ,कुलदीप, जगदीप मांजू पुत्रगण रामसिंह मांजू को जारी किया गया है। कार्यालय हाजा द्वारा उक्त पट्टा विलेख के सन्दर्भ में में परिवादी श्री खुर्शीद पुत्र इस्माईल खां निवासी मौहल्ला बटवालान झुंझुंनू द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर लिखा है कि भूखण्ड संख्या 07 स्टेशन रोड़ के पूर्व का क्षैत्र , क्षैत्रफल 700 वर्गगज का पट्टा विलेख श्री संदीप ,प्रदीप ,कुलदीप, जगदीप मांजू पुत्रगण रामसिंह मांजू के पक्ष में जारी किया गया है। उक्त पट्टा विलख कुटरचित मिथ्या दस्तावेज पेश करते हुये प्राप्त किया गया है। पट्टा विलेख मे खसरा संख्या 2988 अंकित किया गया है,जबकि आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत क्रय दस्तावेज में कोई खसरा संख्या उल्लेखित नहीं है। खसरा संख्या 2988 के पुराना खसरा संख्या 759/1 राजस्व रिकार्ड में इस्माईल पुत्र जहुर खां उर्फ जुहरा खां के नाम दर्ज है। मेरे पिता द्वारा अपने जीवनकाल में भूमि का बेचान नहीं किया गया है। उक्त भूमि पर हम वारीसान का अधिकार है। इसलिये उक्त पट्टा निरस्त किये जाने बाबत निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत परिवाद की सुनवाई करने हेतु कार्यालय पत्रांक 3128 दिनांक 24.06.24 जारी कर दिनांक 28.06.24 को प्रातः 11:00 बजे मय ठोस साक्ष्य उपस्थित होने का जारी किया गया, जिसके कम में पट्टाधारको द्वारा दिनांक 28.06.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जवाब दिये जाने हेतु समय की मांग की गई। परिवाद के सन्दर्भ में नगरपरिषद् के विधि सलाहकार से विधिक राय प्राप्त की गयी , प्राप्त विधिक रिपोर्ट अनुसार " **आवेदकगण द्वारा कय भूमियों से अधिक भूमि रास्ते की भूमि को शामिल करते हुए हस्तगत पट्टा प्राप्त किया गया है तथा पत्रावली संलग्न पीएस कोतवाली झुन्झुनू की अन्तिम रिपोर्ट में आवेदकगण को धारा 199 आईपीसी के अपराध का आरोपी माना है, जिससे प्रकट होता है कि आवेदकगणों द्वारा प्रथम दृष्ट्या मिथ्या दस्तावेजात एवं घोषणा पत्रावली के आवेदन के साथ संलग्न की है, जिसके संबंध में नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 ख के प्रावधानो के अनुसार हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् नगरपालिका को पट्टे व उससे संबंधित प्रस्ताव या कार्यवाही को पूर्णतः या भागतः उपान्तरित, रद्द या विखण्डित करने का अधिकार निहित है। इसलिए उक्त पत्रावली में हितबद्धपक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का नोटिस देकर उक्त पट्टे के संबंध में 73(ख) अनुसार कार्यावाही सम्पादित की जानी उचित होगी**"

परिवाद की जांच करने पर संज्ञान में आया कि आवेदकगणों द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्रों के 55.55 वर्गगज(प्रदीप मान्जू), 55.55 वर्गगज (संदीप मान्जू), 250.00 वर्गगज (जगदीप मान्जू), 250.00 वर्गगज (कुलदीप मान्जू) क्रय किया गया है। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्रों में 10'0" रास्ता दर्शाया गया है। आवेदकगणों द्वारा उक्त कय की गयी भूमि 611.10 वर्गगज + रास्ते की भूमि 110'0"*10'0"=122.22 वर्गगज कुल क्षेत्र. 733.33 वर्गगज का पट्टा चाहने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसका अनुमोदित ले आउट प्लान के अनुसार क्षैत्रफल, सड़क की चौड़ाई मध्य से 50 फीट होने के कारण 700 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया है किन्तु उक्त जारी पट्टा विलेख में रास्ते की भूमि का पट्टा जारी हुआ है। उक्त रास्ते की भूमि का पट्टा पट्टाधारको द्वारा मिथ्या दस्तावेजात प्रस्तुत कर प्राप्त किया गया है।

कार्यालय पत्रांक 3128 दिनांक 24.06.24 के कम में पट्टा धारको द्वारा अनुचित समयावधि की मांग की गयी, जो स्वीकार्य नही होने , प्राप्त विधिक राय के अनुसार एवं पत्रावली अंकित तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार पट्टाधारको को सुनवाई का अंतिम अवसर प्रदान करते हुये कार्यालय पत्रांक 3266 दिनांक 28.06.2024 से पट्टाधारको द्वारा कय की गई भूमि से अधिक भूमि का पट्टा विलेख प्राप्त किये जाने के सन्दर्भ में अपना स्पष्टीकरण/जवाब दिनांक 01.07.2024 को प्रातः 11:00 बजे तक प्रस्तुत किये जाने हेतु जारी किया गया। जिसके कम में पट्टाधारको द्वारा कोई तथ्य/ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री संदीप ,प्रदीप ,कुलदीप, जगदीप मांजू पुत्रगण रामसिंह मांजू द्वारा उक्त पट्टा विलेख आवेदन में मिथ्या तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर प्राप्त किया गया है। अतः स्वायत शासन नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.05.2012 की धारा 34 व राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(ख) के अधीन उपरोक्त जारी पट्टा विलेख दिनांक 21.06.2013 से संबंधित समस्त राशि को राजसात करते हुए उक्त पट्टा विलेख दिनांक 21.06.2013 को निरस्त किया जाता है। उक्त पट्टे के आधार पर जारी किसी भी प्रकार की स्वीकृति/अन्तरण को भी निरस्त समझा जावे।

यह पट्टा निरस्तीकरण आदेश मेरे हस्ताक्षर और मोहर के अधीन आज दिनांक 05.07.2024 .को जारी किया गया है।

राज.संवाद/सी/24/2065

आयुक्त

'प्रदेश के विकास को दिशा और गति देगा बजट'

चूरू, (कासं.)। भारतीय जनता पार्टी के नेता पद्मभूषण देवेंद्र झाझड़िया ने राज्य सरकार की ओर से बुधवार को पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए बजट को राजस्थान के विकास की दिशा और गति तय करने वाला बताया है। झाझड़िया ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार हर वर्ग और हर क्षेत्र को तवज्जो दी गयी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकसित राजस्थान/2047 के लक्ष्य के साथ आगामी 5 वर्ष की कार्ययोजना के तहत 10 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आज सदन में वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट प्रस्तुत करते हुए विकसित और उन्नत राजस्थान के ध्येय को चरितार्थ करते हुए प्रदेश के युवा, किसान, मजदूर, महिला व विद्यार्थी वर्ग के लिए विभिन्न उत्कृष्ट योजनाएँ प्रारम्भ करने की घोषणा की है।

सरपंचों ने विभिन्न मांगों को लेकर दिया धरना

चिड़ावा, (निसं)। सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश व्यापी आव्हान पर चिड़ावा ब्लॉक में उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर सरपंच संघ के बैनर तले सरपंचों ने धरना दिया और उपखंड अधिकारी, विधायक पितराम काला, सांसद बृजेन्द्र ओला और पंचायत समिति विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया। सरपंच संघ चिडावा के अध्यक्ष विनोद डांगी व सचिव संजय सैनी ने बताया कि सरपंच संघ 14 सूत्री मांगों को लेकर अन्दोलनरत है। उनमें मुख्य मांगे करीब 2 साल से बकाया चल रहे एसएफसी, एफएफसी की करीब 7700 करोड़ की किस्तों के भुगतान, मनरेगा की बकाया राशि का भुगतान, जल जीवन मिशन का संचालन जलदाय विभाग को सौंपने, सरपंचों के मानदेय में बढ़ोतरी, समायोजन के नाम पर सरपंचो का शोषण बन्द कर नियमानुसार समायोजन करवाने, खाद्य सुरक्षा में नए परिवारों को जोड़ने आदि प्रमुख हैं ।

आंदोलन के चलते सरकार ने 1100 करोड़ की कुछ राशि का भुगतान किया है, लेकिन ये अभी नाकाफी है । सरपंचों ने आंदोलन जारी रखने की बात कही है। आंदोलन ने तहत अब 12 जुलाई को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। फिर भी मांगे नही मानी गई तो 18 जुलाई को विधनसभा का घेराव किया जाएगा।

ज्ञापन देने वालों में सरपंच विनोद डांगी ओजटू, संजय सैनी लाम्बा गोठड़ा, अनिल कटेवा बख्तावरपुरा, उम्मेद सिंह बराला सारी, सुब. महावीर सिंह खुडाना, सरपंच प्रतिनिधि जंग्शेर अली गिडानिया, शीशराम धतरवाला, आशीष झाझडिया नारी, इन्द्राज सिंह , विजय सिंह श्योपुरा आदि शामिल रहे।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 57/2027

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री चुन्नीलाल पूनियां पुत्र शोलाराम जी पूनियां, ग्राम पोस्ट नाहरसिंघानी, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास आर्शीवाद बालाजी मंदिर ट्रस्ट, ग्राम पोस्ट नाहरसिंघानी तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 08.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइंदा तारीख पेशी 12.09.2024

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग, जयपुर

'झुंझुनूं के साथ सौतेला व्यवहार किया'

झुंझुनूं, (निसं)। कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा ने बुधवार को राज्य के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे नए पैकेट में पुरानी चीज बताया है। सुंडा ने कहा कि झुंझुनूं जिले के साथ सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। गहलोत सरकार ने चिड़ावा और खेतड़ी की सीएचसी को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत कर उनके भवन के लिए बजट का प्रावधान किया था। लेकिन नई सरकार ने पहले तो इसे रोका और अब अपने बजट में शामिल कर उप जिला अस्पताल के नाम पर वाहवाही लूटना चाहती है।

यही हालत इंदिरा नहर परियोजना का है। झुंझुनूं जिले के हर क्षेत्र को कांग्रेस ने इस परियोजना से जोड़ने का फैसला ले लिया था। मंडावा, खेतड़ी और झुंझुनूं विधानसभा क्षेत्रों में हर घर में पानी पहुंच रहा है। उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ विधानसभा में कांग्रेस सरकार ने बजट देकर टेंडर तक की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वहीं पिलानी व नवलगढ़ के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं हुई। भाजपा ने तकनीकी स्वीकृति नहीं दी और वित्तीय स्वीकृति को भी निरस्त कर दिया। अब पूर्व में स्वीकृत योजना के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यही हाल यमुना नहर के पानी की डीपीआर के नाम पर है। ताजेवाला हैड से पूर्व में आवंटित पानी की बजाय कम पानी पर राजस्थान डीपीआर तैयार कर हरियाणा के सामने विवश साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी साजिश तो बजट में खेल यूनिवर्सिटी के नाम पर रची गई है। एक बार फिर भाजपा, खेल यूनिवर्सिटी को दूसरी जगह ले जाने का खेल इस बजट में खेल गई है। झुंझुनूं की खेल यूनिवर्सिटी को लेकर बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा। वहीं एक नई महाराणा प्रताप खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात कही गई है। जिससे स्पष्ट है कि भाजपा झुंझुनूं जिले का विकास नहीं चाहती। जो विकास झुंझुनूं में होना चाहिए। उसे भी दूसरे रास्तों से दूसरी जगह ले जा रही है। लेकिन कांग्रेस महाराणा प्रताप खेल यूनिवर्सिटी का कोई विरोध नहीं है। पर झुंझुनूं की खेल यूनिवर्सिटी को दूसरी जगह नहीं जाने दिया जाएगा। सुंडा ने कहा कि नवलगढ़ में नगरपालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने, शौर्य उद्यान के लिए बजट देने, पुलिस लाइन के पुलिया के निर्माण के लिए बजट देने जैसे कई मुद्दे ऐसे है। जिन्हें सुलझाने के लिए भाजपा के मंत्रियों से लेकर झुंझुनूं के भाजपा नेताओं तक ने दौरे किए। फोटो खिंचवाई और दावा किया कि इन कामों के लिए बजट देंगे।